



लोक सभा/राज्य सभा के पटल पर
रखे जाने वाले कागज
अधिप्रमाणित

डॉ. जितेन्द्र सिंह

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार),
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय,
राज्य मंत्री प्रधान मंत्री कार्यालय,
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय,
परमाणु उर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष मंत्रालय,
भारत सरकार

संक्षिप्त रिपोर्ट

2019-20

राष्ट्रीय सुशासन केंद्र

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार का स्वायत्त संस्थान

वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 का सार

राष्ट्रीय सुशासन केंद्र

केंद्र के बारे में :

राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार के तत्वावधान में एक स्वायत्त संस्थान है।

राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) की स्थापना अध्ययनों, प्रशिक्षण, ज्ञान की साझेदारी और उत्तम विचारों के प्रोत्साहन के जरिए शासन में सुधार लाने हेतु सहायता करने के उद्देश्य से की गई है। इससे नीति संगत शोध कार्य करने एवं मामला अध्ययन तैयार करने, भारत और अन्य विकासशील देशों के सिविल सेवकों के लिए सहायक क्षमता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करने, मौजूदा ज्ञान के आदान-प्रदान हेतु मंच उपलब्ध कराने और राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सक्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करने तथा उनके कार्यान्वयन के लिए विचार विकसित करने की अपेक्षा की जाती है।

अधिदेश :

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर शासन और लोक नीति पर क्षमता निर्माण के जरिए सुशासन को प्रोत्साहन, शासन से संबंधित मुद्दों पर अध्ययन-कार्य करना, बेहतर प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए परामर्श, कार्यशालाओं, सेमिनारों, वार्ताओं का आयोजन करना और नागरिक केंद्रिक शासन के लिए पहल-कार्य करना।

उद्देश्य

राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के उद्देश्य और कार्य इस प्रकार हैं :

- i. नागरिक केंद्रिक सुशासन सुधारों - प्रशासनिक, सामाजिक, वित्तीय और राजनीतिक के मार्गदर्शन और कार्यान्वयन में देश का शीर्ष विचार-मंडल होना।
- ii. श्रेष्ठ कार्य-प्रणालियों, पहल और पद्धतियां जो सुशासन, ई-गवर्नेंस पहल, परिवर्तन-प्रबंधन और सरकार के भीतर क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करें, के राष्ट्रीय सूचना कोष के रूप में कार्य करना।
- iii. शासन के मुख्य मुद्दों के समाधान के प्रति कार्य करना, नीति और कार्यक्रम कार्यान्वयन का विश्लेषण, कार्य योजनाओं का विकास, शासन सुधार में सहायता करना तथा विभिन्न क्षेत्रों एवं भारत सरकार के मंत्रालयों/ विभागों और राज्य सरकारों के बीच सहक्रियाशीलता विकसित करने में सहायता प्रदान करना।
- iv. विनियामक और विकासात्मक प्रशासन, शहरी एवं क्षेत्रीय आयोजना, स्थायी विकास, सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रम तथा कृषि क्षेत्र के मुद्दों पर विशेष संदर्भ सहित लोक प्रबंधन/ लोक नीति के विभिन्न पहलुओं पर शोध कार्य शुरू करना।
- v. विभिन्न सरकारी, गैर-सरकारी तथा विदेशी एजेंसियों द्वारा प्रवर्तित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समन्वयन और आयोजन। एनसीजीजी, केंद्र/ राज्य सरकारों के संगठनों और केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों एवं राज्य एटीआई को शोध-पत्रों, शासन सुधार पर श्रेष्ठ कार्य-प्रणालियों, नीति विश्लेषण

एवं विकल्प के रूप में शासन और प्रबंधन के मुद्दों पर निदेश, मार्गदर्शन एवं क्षमता निर्माण इनपुट्स उपलब्ध कराएगा।

- vi. लोक हित में नीतियां अपनाने एवं लागू कराने के संबंध में सहमति बनाने की दृष्टि से सभी स्टैकहोल्डरों को सम्मिलित करते हुए सामयिक मुद्दों पर राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन करना। सरकार के बाहर एवं भीतर, अन्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ संवाद, पारस्परिक हित के विषयों पर शोध-कार्य और प्रशिक्षण।

शासी निकाय और प्रबंधन समिति

राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) मंत्रिमंडल सचिव, भारत सरकार की अध्यक्षता में शासी निकाय तथा सचिव, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार की अध्यक्षता में प्रबंधन समिति द्वारा संचालित होती है।

वर्ष 2019-20 के दौरान एनसीजीजी के कार्यकलाप

I. कार्यशालाएं/ सेमिनार

- क. पुलिस सुधार दिवस, 2019 एवं प्रधानमंत्री के स्मार्ट पुलिस की परिकल्पना को साकार करने पर राष्ट्रीय सेमिनार (नागरिक केंद्रिक शासन में नवाचार)

II. प्रशिक्षण कार्यक्रम

अंतरराष्ट्रीय

- क. एनसीजीजी ने बंगलादेश के सिविल सेवकों के लिए 05 फील्ड प्रशासन में क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।
ख. मालदीव के सिविल सेवकों के लिए 05 क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम।
ग. म्यांमार के नगर प्रशासकों के लिए 03 मिड-कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम।
घ. गैम्बिया सिविल सेवकों के लिए 02 विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम।
ड. कंबोडियाई सिविल सेवकों के लिए नेतृत्व और ई-गवर्नेंस पर 01 प्रशिक्षण कार्यक्रम।

राष्ट्रीय

- क. एनसीजीजी-आईआईसीए ने गुजरात सरकार के अधिकारियों के लिए 02 व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए।
ख. राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र जैसेकि असम, ओडिशा और मध्य प्रदेश के लिए लोक नीति और शासन पर 02 प्रशिक्षण कार्यक्रम।
ग. एनसीजीजी ने राज्य सभा और लोक सभा के वरिष्ठ अधिकारियों तथा कोल इंडिया लिमिटेड के वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए 05 प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किए।